

इच्छा-मृत्यु के लिये 'लविगि वलि' का औचित्य

संदर्भ

कोमा जैसी स्थिति में पहुँचने पर क्या किसी शख्स को खुद को ज़िन्दा रखने या इच्छा-मृत्यु चुनने का अधिकार दिया जा सकता है? वदिति हो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवधान पीठ सुनवाई कर रही है। केंद्र ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यदि इच्छा-मृत्यु को मंजूरी दी गई तो इसका दुरुपयोग हो सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि एनजीओ 'कॉमन कॉज' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखल कर कहा था कि संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरह नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह उन्हें मरने का भी अधिकार है।
- जबकि केंद्र सरकार का मानना है कि इच्छा-मृत्यु की वसीयत (लविगि वलि) लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, हालाँकि मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर मरणासन्न व्यक्तिका 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' हटाया जा सकता है।

क्या है केंद्र सरकार के तर्क?

- केंद्र सरकार का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में पैसवि यूथनेशिया (कोमा में पड़े मरीज़ का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना) सही तो है, लेकिन वह लविगि वलि का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि यह एक तरह से आत्महत्या जैसा है।
- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मशिरा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संवधान पीठ के समक्ष सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि पैसवि यूथनेशिया को लेकर वधियक का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

संबंधित वधियक में क्या?

- लॉ कमीशन की सफ़ारिश के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पैसेंट (प्रोटेक्शन ऑफ पेसेंट एंड मेडिकल प्रैक्टिसनर्स) बिल' का मसौदा तैयार किया गया है।
- संबंधित वधियक यह सुनिश्चित करेगा कि असाध्य और भयंकर पीड़ा देने वाली बीमारी से पीड़ित मरीज़ों को इलाज से मना करने की यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की इज़ाज़त है या नहीं।
- इस वधियक में यह कहा गया है कि पैसवि यूथनेशिया के मामले में मेडिकल बोर्ड यह निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होगा कि मरीज़ से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाना चाहिये या नहीं।

एक्टवि और पैसवि यूथनेशिया में अंतर क्या है?

- 'एक्टवि यूथनेशिया' और 'पैसवि यूथनेशिया' इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग 'इच्छा-मृत्यु' को इंगति करने हेतु किया जाता है। 'एक्टवि यूथनेशिया' वह स्थिति है, जब इच्छा-मृत्यु मांगने वाले किसी व्यक्तिका इस कृत्य में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे- ज़हरीला इंजेक्शन लगाना आदि।
- वहीं पैसवि यूथनेशिया वह स्थिति है जब इच्छा-मृत्यु के कृत्य में किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती।
- एक वाक्य में कहें तो एक्टवि यूथनेशिया वह है, जिसमें मरीज़ की मृत्यु के लिये कुछ किया जाए, जबकि पैसवि यूथनेशिया वह है जहाँ मरीज़ की जान बचाने के लिये कुछ न किया जाए।

क्या 'लविगि वलि' बनाना उचित है?

- एनजीओ कॉमन कॉज ने इस मसले पर याचिका दाखल की थी कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को 'लविगि वलि' बनाने का हक मिला चाहिये।
- दरअसल, लविगि वलि बनाना इसलिये उचित नज़र आता है, क्योंकि 'लविगि वलि' के माध्यम से ही कोई शख्स यह बता सकेगा कि जब उसके ठीक होने की उम्मीद न हो तो उसे ज़बरन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना उचित है या नहीं?
- लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 'लविगि वलि' की इज़ाज़त केवल पैसवि यूथनेशिया के मामलों में ही दी जानी चाहिये।
- कोमा में पहुँच चुका मरीज़ खुद इस स्थिति में नहीं होता कि वह अपनी इच्छा व्यक्त कर सके। इसलिये उसे पहले ही ये लिखने का अधिकार होना चाहिये कि जब उसके ठीक होने की उम्मीद खत्म हो जाए तो उसके शरीर को यातना न दी जाए।
- हालाँकि बड़ा सवाल यह है कि कोई यह कैसे तय कर सकता है कि उसके शरीर को बाद में यातना झेलनी पड़ेगी। अतः वह पहले ही 'लविगि वलि' पर हस्ताक्षर कर दे?

- इस संबंध में एक उपाय यह हो सकता है कि डॉक्टरों की एक टीम द्वारा संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य की भलीभाँति जाँच की जाए, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अभाव में ऐसा नहीं हो पाता है।

नषिकर्ष

- इच्छा-मृत्यु के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि "संवधान में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है, परंतु इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होता है"।
- हालाँकि, कुछ अंतरराष्ट्रीय कानूनों में जीवन के अधिकार के साथ-साथ इच्छा-मृत्यु के अधिकार को भी स्वीकार किया गया है।
- बीमार व्यक्तियों के लिये इच्छा-मृत्यु यानी बिना कष्ट के मरने के अधिकार की मांग अक्सर होती रही है। वदिति हो कल्लो कमीशन भी संसद को दी अपनी एक रपौरट में पैसवि यूथेनेशिया को कानूनी जामा पहनाने की सफारिश कर चुका है।
- वर्तमान मामले में भले ही बहस लविगि वलि पर केन्द्रति है, लेकिन यह आवश्यक जान पड़ता है कि असाध्य रोगों से पीड़ति व्यक्ति को सम्मानजनक मौत मलि, हालाँकि इससे संबंधति तमाम नैतिक एवं वैधानकि आयामों पर एक व्यापक बहस के बाद ही इस संबंध में आगे कदम बढ़ाना चाहिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/impotance-of-living-will-to-die>

